



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 499]
No. 499]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 17, 2006/आश्विन 25, 1928
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 17, 2006/ASVINA 25, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2006

(आयकर)

सा.का.नि. 645(अ).—जबकि, भारत गणराज्य की सरकार तथा किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की सरकार के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा कर अपवंचन की रोकथाम के लिए अनुबद्ध अभिसमय उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 28 के अनुसार 1 नवम्बर, 2006 से प्रवृत्त होगा जो उस मास जिसमें इस अभिसमय को प्रवृत्त करने के लिए संबंधित कानूनों द्वारा यथा अपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरा होने के उपरांत परवर्ती अधिसूचनाएं प्राप्त हुई थीं, के पश्चात् दूसरे मास का प्रथम दिन है।

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा यह निदेश देती है कि उक्त अभिसमय के सभी प्रावधानों को भारत संघ में प्रभावी किया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 287/2006-एफ टी डी/फा. सं. 501/7/91-विक्रप्र]

पूनम दत्त, संयुक्त सचिव

अनुबंध

आय पर करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के परिहार और कर अपवंचन को रोकने के लिए,

भारत गणराज्य की सरकार

और

सऊदी अरब किंगडम की सरकार

के बीच

अभिसमय

भारत गणराज्य की सरकार तथा सऊदी अरब किंगडम की सरकार, आय पर करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के परिहार तथा कर अपवंचन को रोकने के लिए और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के संवर्द्धन की दृष्टि से एक अभिसमय निष्पन्न करने की इच्छा से, निम्नानुसार सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद-1

शामिल व्यक्ति

यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा, जो सविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं।

अनुच्छेद - 2**सन्मिलित कर**

1. यह अभिसमय किसी संविदाकारी राज्य अथवा इसके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से आय तथा पूंजी पर लगाए गए करों पर लागू होगा, चाहे ये कर किसी भी प्रकार से लगाए जाएं।

2. सकल आय अथवा आय के तत्वों पर लगाए गए सभी करों को आय पर लगने वाले करों के रूप में माना जाएगा जिनमें चल और अचल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर कर, उद्यमों द्वारा अदा किए गए वेतनों और मजदूरियों की सकल रकम पर कर शामिल है।

3. जिन वर्तमान करों पर यह अभिसमय लागू होगा वे विशेषकर इस प्रकार हैं :

(क) भारत के मामले में :

- आयकर जिसमें उस पर लगने वाला कोई अधिभार भी शामिल है ;
(जिसे इसके बाद “भारतीय कर” कहा जाएगा);

(ख) सऊदी अरब किंगडम के मामले में :

- जकत
- प्राकृतिक गैस निवेश कर सहित आयकर ;

(जिसे इसके बाद “सऊदी कर” कहा जाएगा)।

4. इस अभिसमय के उपबंध किसी भी सस्रुम अथवा तत्वतः समान करों पर भी लागू होंगे, जो इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् किसी एक संविदाकारी राज्य द्वारा विद्यमान करों के अलावा अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे। दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी क्रमशः अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे एक-दूसरे को अभिसूचित करेंगे।

अनुच्छेद - 3**सामान्य परिभाषाएं**

1. इस अभिसमय के प्रयोजनों के लिए जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

- (क) “भारत” पद से अभिप्रेत है - भारत का राज्यक्षेत्र, और इसमें राज्यक्षेत्रीय समुद्र और उसके उमर आकाशीय क्षेत्र के साथ-साथ अन्य समुद्री क्षेत्र भी शामिल हैं जिनमें समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय सहित भारतीय कानून तथा अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हैं ;

- ख) “सऊदी अरब किंगडम” पद का अर्थ सऊदी अरब किंगडम के उस क्षेत्र से है जिसमें क्षेत्रीय जल के बाहर के वे क्षेत्र भी शामिल हैं जहां सऊदी अरब किंगडम अपने प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकारों तथा क्षेत्राधिकारों का अपने जल, समुद्र, अवमृदा तथा प्राकृतिक संसाधनों का अपने कानून और अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार प्रयोग करता हो ;
- ग) “एक संविदाकारी राज्य” तथा “दूसरा संविदाकारी राज्य” पद का अर्थ, संदर्भ की अपेक्षानुसार भारत गणराज्य अथवा सऊदी अरब किंगडम से है ;
- घ) “व्यक्ति” पद में कोई व्यक्ति, कोई कम्पनी, व्यक्तियों का कोई संगठन शामिल है ;
- ङ.) “कम्पनी” पद से कोई निगमित निकाय अथवा कोई ऐसी सत्ता अभिप्रेत है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय के रूप में समझा जाता है ;
- च) “एक संविदाकारी राज्य का उद्यम” तथा “दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम” पदों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है ;
- छ) “अन्तरराष्ट्रीय यातायात” पद से अभिप्रेत है - किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा कोई भी परिवहन जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित हो सिवाए उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो ;
- ज) “सक्षम प्राधिकारी” पद का अर्थ है :-
- (i) भारत के मामले में : वित्त मंत्री, भारत सरकार अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि ;
 - (ii) सऊदी अरब किंगडम के मामले में : वित्त मंत्रालय जिसका प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि करे ;
- झ) “राष्ट्रिक” पद का अर्थ है :
- (i) किसी संविदाकारी राज्य की राष्ट्रिकता धारण करने वाला कोई व्यक्ति ;
 - (ii) कोई विधिक व्यक्ति, भागीदारिता अथवा संगठन जिसे इस की यह हैसियत संविदाकारी राज्य में लागू कानूनों से प्राप्त होती हो ।

2. जहां तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी भी समय इस अभिसमय को लागू किए जाने का प्रश्न है, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उसमें अपरिभाषित किसी शब्द का वही अर्थ होगा जो करों के प्रयोजनार्थ उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत उस समय था, जिस पर यह अभिसमय लागू होता है और उस राज्य पर लागू कर कानूनों के अंतर्गत यह अर्थ उस राज्य के किन्हीं अन्य कानूनों के अंतर्गत लगाए गए अर्थ पर प्रभावी होगा ।

अनुच्छेद -4

निवासी

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ “एक संविदाकारी राज्य का निवासी” पद का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से है

(क) जिसपर उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास, प्रबन्ध - स्थान अथवा किसी ऐसी ही कसौटी के कारण कर लगाया जा सकता है। परन्तु इस पद में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं होगा जिसपर केवल उस राज्य के स्रोतों पर होने वाली आय पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है ;

(ख) दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक की सरकार अथवा इसका कोई राजनयिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण ।

2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों ही संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी :

क) उसे केवल उसी राज्य का निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, यदि उसे दोनों ही राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, तो वह उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र) ;

ख) यदि उस राज्य का जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निश्चय नहीं किया जा सकता हो अथवा यदि उसको दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो ;

ग) यदि वह आदतन दोनों ही राज्यों में रहता हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह एक राष्ट्रिक है ;

घ) यदि वह दोनों ही राज्यों का राष्ट्रिक हो अथवा उनमें से किसी राज्य का भी राष्ट्रिक है तब संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे ।

3. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण किसी व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति दोनों ही संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तब उसे केवल उसी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका प्रभावी प्रबंध - स्थान स्थित है ।

अनुच्छेद -5**स्थायी संस्थापन**

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ “स्थायी संस्थापन” पद का आशय कारोबार के उस निश्चित स्थान से अभिप्रेत है, जिसके द्वारा किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाता है।

2. “स्थायी संस्थापन” पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे :

- (क) प्रबंध का कोई स्थान ;
- (ख) कोई शाखा ;
- (ग) कोई कार्यालय ;
- (घ) कोई कारखाना ;
- (ङ.) कोई कार्यशाला ;
- (च) कोई खान, तेल अथवा गैस का कुआँ, कोई खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान ;

3. “स्थायी संस्थापन” पद में निम्नोक्त भी शामिल होंगे :

- (क) कोई भवन-स्थल, कोई निर्माण, प्रस्थापन अथवा संयोजन परियोजना अथवा उससे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलाप परन्तु केवल वहीँ जहाँ ऐसा भवन स्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप 182 दिनों से अधिक समय तक चलता रहता हो।
- (ख) किसी उद्यम द्वारा अपने कर्मियों द्वारा अथवा इस प्रयोजनार्थ उद्यम द्वारा लगाए गए व्यक्तियों के माध्यम से परामर्शदायी सेवाओं सहित सेवाएं मुहैया करवाना परन्तु जहाँ इस किस्म के कार्यकलाप (इसी अथवा किसी सम्बद्ध परियोजना हेतु) देश के भीतर 12 माह की अवधि में कुल मिलाकर 182 दिन से अधिक की अवधि तक जारी रहें।

4. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी “स्थायी संस्थापन” पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं समझा जाएगा :

-
- (क) उस उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं के मात्र भण्डारण, प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का इस्तेमाल करना ;
 - (ख) मात्र भण्डारण, प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ उक्त उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य वस्तुओं के किसी स्टॉक का रख-रखाव करना ;

- (ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उस उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के स्टॉक का रख-रखाव करना ;
- (घ) उस उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं का केवल क्रय करने के लिए अथवा सूचना एकत्र करने के लिए कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना ;
- (ङ.) उस उद्यम के लिए मात्र कारोबार चलाने के लिए निश्चित स्थान का रख-रखाव करना जो प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के हों ;
- (झ) उप-पैराग्राफ (क) से (ङ.) तक में उल्लिखित कार्य-कलापों के संयोजन के लिए मात्र व्यापार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना, बशर्ते कि इस संयोजन के परिणामस्वरूप कारोबार के निश्चित स्थान का समस्त कार्यकलाप किसी प्रारम्भिक या सहायक स्वरूप का हो ।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां किसी स्वतंत्र हैसियत के अभिकर्ता, जिस पर पैराग्राफ लागू होता हो, से भिन्न कोई व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से कार्य कर रहा हो, तो उस उद्यम का प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में किन्हीं ऐसी गतिविधियों के संबंध में स्थायी संस्थापन का होना तभी समझा जाएगा, यदि वह व्यक्ति उद्यम के लिए करता हो, यदि यह व्यक्ति ;

(क) उसे उस उद्यम की तरफ से उस राज्य में संविदाएं सम्पन्न करने का प्राधिकार प्राप्त हो और वह आदतन ऐसे प्राधिकार का प्रयोग करता हो, जब तक कि उसके कार्यकलाप इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 4 में उल्लिखित कार्यकलापों तक सीमित न हों, यदि ऐसा कारोबार के किसी निश्चित स्थान से किया जाए इससे उस पैराग्राफ के उपबंधों के अधीन कारोबार के इस निश्चित स्थान को एक स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा ; अथवा

(ख) उसके पास ऐसा कोई प्राधिकार प्राप्त नहीं हो, किन्तु वह प्रथमोल्लिखित राज्य में ऐसे माल अथवा पण्य-वस्तुओं का एक स्टॉक आदतन रखता हो, जिसमें से वह नियमित रूप से उद्यम की ओर से माल और पण्य-वस्तुओं की डिलीवरी करता हो ; अथवा

(ग) वह आदतन प्रथमोल्लिखित राज्य में उद्यम के लिए पूर्णतया अथवा लगभग पूर्णतया आदेश प्राप्त करता हो ।

6. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी किसी संविदाकारी राज्य के किसी बीमा उद्यम का, दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन होना तभी माना जाएगा, यदि वह स्वतंत्र हैसियत वाले किसी एजेंट, के अलावा जिस पर पैराग्राफ 7 लागू होता हो, किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से उस अन्य राज्य के क्षेत्र में बीमे की प्रीमियम एकत्र करता है अथवा वहां स्थित जोखिमों का बीमा करता है ।

7. किसी उद्यम का किसी संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन का होना नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों। तथापि, जब ऐसे किसी एजेंट के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः उस उद्यम की ओर से किए जाते हों, तो उसे इस पैराग्राफ के अभिप्राय के अंतर्गत स्वतंत्र हैसियत का एजेंट नहीं समझा जाएगा।

8. यदि कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती है अथवा किसी ऐसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे राज्य में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार करती है तो मात्र इस तथ्य से ही उन दोनों में से किसी कम्पनी को स्वतः ही दूसरे का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा।

अनुच्छेद - 6

अचल सम्पत्ति से आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति (कृषि अथवा वानिकी से प्राप्त आय सहित) से प्राप्त आय पर दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. “अचल सम्पत्ति” पद का अर्थ वही होगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसका अर्थ है जिसमें संबंधित सम्पत्ति स्थित है। इस पद में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे - अचल सम्पत्ति के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भण्डार, स्रोत तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन के लिए अथवा कार्य करने के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार। जलयान, नौकाएं, वायुयान और अचल सम्पत्ति के रूप में नहीं समझे जाएंगे।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये पर देने अथवा इसके किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से उद्भूत होने वाली आय पर भी लागू होंगे।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध, किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद - 7

कारोबार से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो। यदि उक्त उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो उस स्थायी संस्थापन को प्राप्त हुए हों।
2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में ऐसे स्थायी संस्थापन के कारण हुए लाभ, वे लाभ माने जाएंगे जिनके होने की तब संभावना रहती है जब वह एक समान या उससे मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक समान या मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगे हुए किसी निश्चित और भिन्न उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता है जिसका वह एक स्थायी संस्थापन है।
3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण करने में उन खर्चों की कटौती की अनुमति दी जाएगी, जो उस स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनार्थ खर्च किए जाते हैं, जिनमें इस प्रकार प्राप्त कार्यकारी एवं सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल हैं, भले ही वे उस राज्य में किए गए हों जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र किए गए हों और ये उस राज्य के स्वदेशी कर कानूनों की सीमाओं के अधीन एवं इस के अनुसरण में किए गए हों। तथापि, स्थायी संस्थापन द्वारा राशियों के संबंध में उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा इसके किन्हीं अन्य कार्यालयों को पेटेंटों अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में रायल्टियों, फीसों अथवा इसी तरह की अन्य अदायगियों के रूप में अथवा कमीशन के रूप में, निष्पादित विशिष्ट सेवाओं के लिए अथवा प्रबंधन के लिए अथवा बैंक उद्यम के मामले को छोड़कर, स्थायी संस्थापन को उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप में (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न) यदि कोई हो, और अदा की गई हों तो उसके संबंध में ऐसी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार एक स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में उस रकम को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जो स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा इसके किसी अन्य कार्यालय को पेटेंटों अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में रायल्टियों, फीसों अथवा इसी तरह की अन्य अदायगियों के रूप में अथवा निष्पादित विशेष सेवाओं अथवा प्रबंधन के लिए कमीशन के रूप में अथवा किसी बैंक उद्यम के मामले को छोड़कर उद्यम अथवा इसके किसी अन्य कार्यालय के कार्यालय प्रमुख को उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप में (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न व्यय) राशियाँ प्रभारित की गई हों।
4. कोई लाभ, केवल इस कारण से किसी स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन ने उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुएं खरीदी हैं।
5. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारण हुए समझे जाने वाले लाभों को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठोस तथा पर्याप्त कारण नहीं हो।

6. जहां लाभों में आय की ऐसी मदें शामिल होती हैं जिनका इस अभिसमय के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद - 8

जहाजरानी और वायु परिवहन

1. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा प्राप्त लाभों पर केवल उस राज्य में ही कर लगाया जाएगा।
2. यदि किसी जहाजरानी उद्यम का प्रभावी प्रबंध स्थान किसी जलयान पर स्थित हो अथवा यदि उस संविदाकारी राज्य जिसका जलयान का प्रचालक एक निवासी हो, में कोई ऐसा घरेलू बन्दरगाह न हो तब उसे उस संविदाकारी राज्य में स्थित माना जाएगा जिसमें जलयान का घरेलू बन्दरगाह स्थित हो।
3. “अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त लाभ” पद में अन्तरराष्ट्रीय परिवहन में प्रयुक्त आधानों और सम्बद्ध उपकरण के प्रयोग अथवा इन्हें किराए पर देने से प्राप्त आय भी शामिल है जो अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त आय के प्रासंगिक हो।
4. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय प्रचालन एजेंसी में भाग लेने से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे।
5. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंध दोहरे कराधान के परिहार हेतु सऊदी अरब किंगडम तथा भारत गणराज्य की सरकार के बीच मौजूदा करार को एयर इंडिया तथा सऊदी अरब एयर लाईन निगम के संबंध में 14.11.1991 में हस्ताक्षरित विमान परिवहन उद्यम के कार्यकलापों से प्राप्त आय पर एक दूसरे को करों से छूट प्रदान कर प्रभावित नहीं करेंगे।

अनुच्छेद - 9

संबद्ध उद्यम

1. जहां
 - (क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है ; अथवा
 - (ख) वे ही व्यक्ति, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं ;

और दोनों में से किसी भी अवस्था में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं तो ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु उन शर्तों के कारण इस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तदनुसार कर लगाया जा सकेगा।

2. जहां एक संविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और तदनुसार कर लगाता है जिस पर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और उसमें सम्मिलित किए गए लाभ ऐसे लाभ हैं जो प्रथमोल्लिखित राज्य के उद्यम को उस स्थिति में प्राप्त हुए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई शर्तें उस तरह की होतीं जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गई होतीं, तब वह दूसरा राज्य उन लाभों पर उसमें प्रभारित कर की राशि के बराबर समुचित समायोजन करेगा। इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में इस अभिसमय के अन्य उपबंधों को यथोचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ परामर्श करेंगे।

अनुच्छेद - 10

लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगे।

2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, उस राज्य के कानूनों के अनुसार भी कर लगाया जा सकेगा, लेकिन, यदि लाभांशों का प्राप्तकर्ता हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार प्रभारित कर लाभांशों की सकल राशि के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे। यह पैराग्राफ, उन लाभों के संबंध में कम्पनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा जिनमें से लाभांश अदा किए जाते हैं।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त “लाभांश” पद का अभिप्राय शेयरों, “ज्योइसेंस” शेयरों या “ज्योइसेंस” अधिकारों, खनन शेयरों, संस्थापन शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय, जो ऋण के दावे न हों, लाभों में हिस्सेदारी से प्राप्त आय तथा अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय है जिस पर वही कराधान अभिक्रिया लागू होती है जो उस राज्य के कानूनों के द्वारा शेयरों से प्राप्त आय पर लागू होती है, जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी एक निवासी है।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है और जिस कारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है वहां वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14, जैसी भी स्थिति हो, के उपबंध लागू होंगे।

5. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, ऐसी स्थिति में वह दूसरा राज्य ऐसे मामलों को छोड़कर उक्त कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर वहां तक किसी प्रकार का कर नहीं लगाएगा, जहां तक कि ऐसे लाभांश दूसरे राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाते हैं, अथवा जहां तक जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती हो, वह उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन या उस दूसरे राज्य में किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध है और न ही उक्त कम्पनी के अवितरित लाभों पर अवितरित लाभ संबंधी कर लगाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हों।

अनुच्छेद - 11

ऋण-दावों से प्राप्त आय

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई ऋण-दावों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. तथापि, ऐसे ऋण-दावों से प्राप्त आय पर उस संविदाकारी राज्य में जिसमें यह उद्भूत हुई है उस संविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार भी कर लगाया जा सकेगा, किन्तु यदि ऋण-दावों से प्राप्त आय का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का एक निवासी है तो इस प्रकार प्रभारित कर, ऋण-दावों से प्राप्त आय की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली ऋण-दावों से प्राप्त आय को उस राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी, बशर्ते कि यह निम्न द्वारा प्राप्त किया जाता हो और हितभागी स्वामित्व के रूप में रखा जाता हो :

(क) दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, किसी राजनयिक उप प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण; अथवा

(ख) (i) भारत के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय निर्यात आयात बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक; और

(ii) सऊदी अरब किंगडम के मामले में सऊदी अरेबिया मोनेटरी एजेंसी; अथवा

(ग) दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा पूर्णतः प्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व प्राप्त और नियंत्रित कोई अन्य वित्तीय संस्थान।

4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त “ऋणदावों से प्राप्त आय” शब्द का आशय सरकारी प्रतिभूतियों और बाण्डों या ऋणपत्रों से प्राप्त आय है जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बाण्डों या ऋणपत्रों से संबंधित प्रीमियम और पुरस्कार शामिल है, चाहे वे बंधकों द्वारा प्राप्त किए गए हों या नहीं और उसे ऋणदाता के लाभों में भागीदारी करने का अधिकार प्राप्त हो या नहीं; और प्रत्येक प्रकार के ऋणदावे तथा अन्य सभी प्रकार की आय जिसमें उस राज्य के जिसमें आय उद्भूत हुई है, कराधान कानूनों के तहत उधार दिए धन से प्राप्त आय शामिल है। विलम्बित अदायगी के लिए अर्थदंड संबंधी प्रभारों को इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ ऋणदावों से प्राप्त आय के रूप में नहीं माना जाएगा।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि ऋण-दावों से प्राप्त आय का हितभागी स्वामी एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें ऋण-दावों से प्राप्त आय उद्भूत हुई हो, स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित एक निश्चित स्थान से वहां स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है और जिस ऋण-दावे के बारे में आय अदा की जाती है वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। इस प्रकार के मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

6. किसी संविदाकारी राज्य में ऋण-दावों संबंधी दावों से प्राप्त आय तब उत्पन्न हुई मानी जाएगी जब ब्याज अदा करने वाला उस राज्य का निवासी हो। तथापि, जहां ऐसी आय अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह एक संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था, जिस पर ऐसी आय की अदायगी की गई थी और इस प्रकार की आय उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती है तब ऐसी आय उस राज्य में उत्पन्न हुई मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहां, अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध होने के कारण अदा की गई ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय की रकम, उस ऋणदावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए यह रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके संबंध में इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध अन्तिम वर्णित रकम पर ही लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगी के आधिक्य भाग पर, इस अभिसमय के अन्य उपबंधों का सम्यक अनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद - 12

रायल्टियां

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायल्टियों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. तथापि, इस प्रकार की रायल्टियों पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत हुई हों और उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा लेकिन यदि रायल्टियों का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का एक निवासी है तो इस प्रकार लगाया गया कर रायल्टियों की सकल रकम के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त “रायल्टियां” शब्द का अभिप्राय है किसी साहित्यिक, कलात्मक, अथवा वैज्ञानिक कृति जिसमें सिनेमाटोग्राफ फिल्मों के कापी राइट का प्रयोग करने का अधिकार या प्रयोग करने हेतु विचार किए जाने के लिए या रेडियो या टेलीविजन प्रसारण हेतु फिल्में अथवा टेपों, कोई पेटेंट, व्यापार चिन्ह डिजाइन या मॉडल योजना, गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया अथवा कोई औद्योगिक वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण अथवा उद्योग,

वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव (जानकारी) से सम्बन्धित सूचना को प्रयुक्त करने या प्रयुक्त करने के अधिकार हेतु प्राप्त की गयी किसी भी प्रकार की अदायगियां ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टियों का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रायल्टियाँ उद्भूत होती हैं, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में रायल्टियाँ अदा की जाती हैं, वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से संबद्ध हैं ऐसे मामले में यथा-स्थिति अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध लागू होंगे ।

5. एक संविदाकारी राज्य में रायल्टियाँ तब उद्भूत हुई मानी जाएंगी, जब अदाकर्ता उस राज्य का निवासी हो । तथापि, जहां रायल्टियाँ अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, उस संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिनके संबंध में रायल्टियाँ अदा करने की जिम्मेदारी निभाई गई हो और ऐसी रायल्टियाँ उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हो, तब ऐसी रायल्टियाँ उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएंगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित हैं ।

6. जहां, अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण किसी प्रयोग, अधिकार अथवा सूचना के संबंध में प्रदत्त रायल्टियों की रकम, उस रकम से बढ़ जाती है जिस पर इस प्रकार के संबंधों की अनुपस्थिति में अदाकर्ता और हितभागी स्वामी में सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर लागू होंगे । ऐसे मामले में, अदायगियों के उस आधिक्य भाग पर इस अभिसमय के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा ।

अनुच्छेद - 13

पूंजीगत अभिलाभ

1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के अंतरण से एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभ पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारोबार संपत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभ पर, जो संपत्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले अभिलाभ भी शामिल हैं, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा ।

3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयान अथवा इस प्रकार के जलयानों अथवा वायुयान के परिचालन से संबंधित चल सम्पत्ति के अंतरण द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा अंतरणकर्ता जिस का निवासी है ।
4. किसी कम्पनी के पूंजीगत स्टॉक जिसकी सम्पत्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति शामिल है, के शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभ पर उस राज्य में कर लग सकेगा ।
5. किसी कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, के पैराग्राफ 4 में उल्लिखित शेयरों से भिन्न शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।
6. पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 और 5 में उल्लिखित के अतिरिक्त किसी सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा, अंतरणकर्ता जिसका निवासी है ।

अनुच्छेद - 14

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी, व्यक्ति द्वारा व्यावसायिक सेवाओं अथवा स्वतंत्र स्वरूप वाले इसी प्रकार के स्वतंत्र कार्यकलापों के निष्पादन से प्राप्त आय, निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर, जब ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा, केवल उसी संविदाकारी राज्य में कराधेय होगी :

(क) यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ, दूसरे संविदाकारी राज्य में नियमित रूप से एक निश्चित स्थान उपलब्ध है तो उस मामले में उस दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल उतनी आय पर ही कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है ; अथवा

(ख) यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके ठहरने की अवधि या अवधियां किसी बारह महीने की अवधि में कुल मिलाकर 183 दिनों अथवा इससे अधिक दिन के लिए हों, या संबंधित राजकोषीय वर्ष में समाप्त हो, तो उस मामले में, आय के केवल उतने ही भाग पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जो उस दूसरे राज्य में उसके द्वारा निष्पादित कार्यकलापों से प्राप्त होती हो ।

2. “व्यावसायिक सेवाएं” पद में विशेषतया स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक या शिक्षण संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तु - विदों, शल्य - चिकित्सकों, दन्त चिकित्सकों और लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप सम्मिलित हैं ।

अनुच्छेद - 15**परावलम्बित वैयक्तिक सेवाएं**

1. अनुच्छेद 16, 18, 19, 20 और 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा जब तक कि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया है। यदि ऐसा नियोजन किया गया है तो जो पारिश्रमिक वहां से प्राप्त होता है, उस पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि :

(क) प्राप्तकर्ता संबंधित वित्तीय वर्ष में आरम्भ होने वाली अथवा समाप्त होने वाली किसी बारह महीने की अवधि में कुल मिलाकर अधिक से अधिक 183 दिन की अवधि या अवधियों के लिए दूसरे राज्य में उपस्थित रहता है ; और

(ख) पारिश्रमिक ऐसे किसी नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया जाता है जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है ; और

(ग) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है, जो नियोजक दूसरे राज्य में रखता हो।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में संचालित जलयान अथवा वायुयान पर किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर उस राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद - 16**निदेशकों की फीस**

निदेशकों की फीस तथा इसी तरह की अन्य अदायगियाँ जो किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी कम्पनी जो अन्य संविदाकारी राज्य की निवासी है, के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में प्राप्त की गई हों, पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

अनुच्छेद - 17

मनोरंजनकर्ता और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार या किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के उसके वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता किसी खिलाड़ी द्वारा अपनी इस प्रकार की हैसियत में किए गए निजी कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो, अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहां उस आय पर अनुच्छेद 7, 14 और 16 के उपबंधों के होते हुए भी, उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी के कार्यकलाप किए जाते हैं।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध मनोरंजनकर्ताओं या खिलाड़ियों द्वारा किसी संविदाकारी राज्य में निष्पादित की गई गतिविधियों से प्राप्त होने वाली आय पर लागू नहीं होंगे यदि ये गतिविधियाँ पर्याप्त रूप से एक या दोनों संविदाकारी राज्यों की सरकारी निधियों या राजनैतिक उप-प्रभागों या उनके स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा वित्तपोषित की जाती है या संविदाकारी राज्यों की सरकारों के बीच किसी सांस्कृतिक करार या प्रबंध के अंतर्गत आयोजित की जाती है। ऐसे मामले में आय केवल उसी संविदाकारी राज्य में कशधेय होगी, जिसका कि मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी निवासी है।

अनुच्छेद - 18

पेंशन

1. अनुच्छेद 19 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधीन एक संविदाकारी राज्य के निवासी को पिछले नियोजन के प्रतिफल के रूप में अदा की गई पेंशन और अन्य ऐसे पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा।

अनुच्छेद - 19

सरकारी सेवा

1. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उस राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उपप्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के संबंध में की गई सेवाओं के लिए किसी व्यक्ति को अदा की गई पेंशन से भिन्न वेतन, मजदूरी और अन्य इसी प्रकार के वेतन, मजदूरी और अन्य इसी प्रकार के पारिश्रमिक पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा।
- (ख) तथापि, ऐसे वेतन, मजदूरी और अन्य इसी प्रकार के पारिश्रमिक पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लगेगा, यदि सेवाएं उस दूसरे संविदाकारी राज्य में की जाती हो और उक्त व्यक्ति उस राज्य का निवासी हो, जो :
 - (i) उस राज्य का एक राष्ट्रिक हो; अथवा
 - (ii) मात्र सेवाएं करने के प्रयोजन से उस राज्य का निवासी नहीं बना हो।
2. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उपप्रभाग अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में किसी व्यक्ति को उस संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उसके द्वारा सृजित निधियों में से या उस के द्वारा अदा की गई पेंशन पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा।
- (ख) तथापि, ऐसी पेंशन पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर तभी कर लगेगा, यदि उक्त व्यक्ति उस संविदाकारी राज्य का एक निवासी तथा राष्ट्रिक हो।
3. अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे किसी कारोबार के सिलसिले में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक तथा पेंशन पर लागू होंगे।

अनुच्छेद-20

विद्यार्थी

- i. अनुदानों, ऋणों और छात्रवृत्ति के अतिरिक्त की गई अदायगियां, जो कोई विद्यार्थी, प्रशिक्षणार्थी अथवा प्रशिक्षु जो किसी संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तुरन्त पहले दूसरे संविदाकारी राज्य का एक निवासी है अथवा था और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ प्रथमोल्लिखित राज्य में उपस्थित है, भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ प्राप्त करता है पर कर नहीं लगाया जाएगा, बशर्ते कि ऐसी अदायगियां उस राज्य के बाहर के स्रोतों से उद्भूत होती हों।

2. किसी विद्यार्थी, प्रशिक्षणार्थी अथवा प्रशिक्षु द्वारा प्राप्त अदायगियां, जो किसी संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तुरन्त पहले दूसरे संविदाकारी राज्य का एक निवासी है अथवा था और जो केवल अपनी शिक्षण अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में उपस्थित है तथा जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में निष्पादित सेवाओं के संबंध में पारिश्रमिक बनती है, उस दूसरे राज्य में कराधेय नहीं होगी, बशर्ते कि सेवाएं, शिक्षण अथवा प्रशिक्षण से संबंधित हों और भरण-पोषण के प्रयोजनार्थ आवश्यक हों।
3. इस अनुच्छेद के लाभ केवल ऐसी अवधि के लिए लागू होंगे जो कि शुरू किए गए शिक्षण अथवा प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अथवा साधारणतया अपेक्षित हों, परन्तु किसी भी स्थिति में, किसी भी व्यक्ति को इस अनुच्छेद के लाभ उस दूसरे राज्य में उसके प्रथमतः पहुंचने की तारीख से लगातार छह वर्षों से अधिक के लिए प्राप्त नहीं होंगे।

अनुच्छेद - 21

अध्यापक और शोधकर्ता

1. कोई अध्यापक अथवा शोधकर्ता, जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा दूसरे ऐसे संस्थान में अध्यापन अथवा शोधकार्य में लगे अथवा दोनों कार्यों के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में आमंत्रित होने अथवा दौरा करने के तुरन्त पहले संविदाकारी राज्य का एक निवासी है अथवा था, पर उस दूसरे राज्य में ऐसे अध्यापन अथवा शोधकार्य के लिए किसी पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में उसके पहुंचने की तारीख से दो वर्षों से अनधिक की अवधि के लिए कर से छूट प्राप्त होगी।
2. यह अनुच्छेद केवल शोधकार्य से प्राप्त आय पर लागू होगा यदि ऐसा शोधकार्य व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक हित में किया जाता है।

अनुच्छेद - 22

अन्य आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदें, जहां-कहीं वे उद्भूत होती हों, जिन पर इस अभिसमय के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, केवल उस संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगी।
2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा-परिभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा ऐसे अधिकार अथवा सम्पत्ति जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे।

अनुच्छेद - 23**दोहरे कराधान के अपाकरण की विधि**

दोहरा कराधान निम्न रूप से निष्प्रभावी होगा :

1. जहां एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को आय प्राप्त होती है जिस पर इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है, वह प्रथमोल्लिखित राज्य उस निवासी की आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में अदा किए गए कर की राशि के बराबर राशि की कर से कटौती की अनुमति देगा ;

तथापि, ऐसी कटौती छूट प्रदान किए जाने से पहले यथा संगणित कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जो मामले के अनुसार उस आय से प्राप्त हुई हो, जिस पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है ।

2. जहां, अभिसमय के किसी उपबंध के अनुसरण में एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अर्जित की गई आय को उस संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त हो, फिर भी वह राज्य ऐसे निवासी की बकाया आय पर कर की राशि की संगणना करते समय छूट प्राप्त आय को ध्यान में रखेगा ।

अनुच्छेद - 24**पारस्परिक करार विधि**

1. जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्यवाहियों के कारण उस पर इस प्रकार कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा जो इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार नहीं है तो वह उन राज्यों के स्वदेशी कानूनों में उपचारों की व्यवस्था होने के बावजूद भी संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक निवासी है । यह मामला उस कार्यवाही की प्रथम अधिसूचना के तीन वर्षों के भीतर अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसके परिणामतः ऐसा कराधान लगाया गया है जो इस अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप नहीं है ।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के परिहार के उद्देश्य से जो इस अभिसमय के अनुरूप नहीं हैं, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ पारस्परिक सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा । इस प्रकार किए गए किसी भी अभिसमय को लागू किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्यों के स्वदेशी कानून में कोई भी समय सीमा क्यों न हो ।

3. इस अभिसमय की व्याख्या करने में अथवा इसे लागू करने में कठिनाइयाँ अथवा शंकाएँ उत्पन्न हों तो दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। वे उन मामलों में भी दोहरे कराधान को हटाने के लिए एक-दूसरे से परामर्श करेंगे जिनके लिए इस अभिसमय में व्यवस्था नहीं की गई हो।

4. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के अभिप्राय से किसी समझौते पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं। जब समझौता करने की दृष्टि से विचारों का मौखिक आदान-प्रदान करना उपयुक्त हो तो ऐसा आदान-प्रदान एक आयोग के माध्यम से किया जा सकता है जिसमें संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि शामिल हों।

अनुच्छेद - 25

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस अभिसमय के उपबंधों को अथवा संविदाकारी राज्यों के उन कर्तव्यों से संबंधित आंतरिक कानूनों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हैं जो इस अभिसमय के अंतर्गत आते हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस अभिसमय के प्रतिकूल नहीं हो। सूचना का आदान-प्रदान करना अनुच्छेद 1 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना उस राज्य के स्वदेशी कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिनमें कोई न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो उन कर्तव्यों का निर्धारण करने अथवा उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा उनसे संबंधित अपीलों का निर्धारण करने में शामिल हों जो इस अभिसमय के अंतर्गत आते हैं। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे प्रयोजन के लिए ही करेंगे। वे सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे।

2. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

- (क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना ;
- (ख) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है ;
- (ग) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वृत्तिका संबंधी गुप्त भेद अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो (आर्डर पब्लिक)।

अनुच्छेद - 26**अन्य उपबंध**

1. इस अभिसमय में कर अपवर्धन को रोकने के लिए आन्तरिक उपबंधों को लागू करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।
2. किसी संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम इस अभिसमय के लाभों को प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा यदि ऐसे उद्यम के सृजन का मुख्य उद्देश्य अथवा एक मुख्य उद्देश्य इस अभिसमय के अंतर्गत लाभों को प्राप्त करना था, जो अन्यथा प्राप्य नहीं होगा ।
3. विधिक हस्तियों के मामले में, जिनके प्रामाणिक व्यावसायिक क्रियाकलाप नहीं हैं, पर इस अनुच्छेद के उपबंध लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 27**राजनयिक मिशन के सदस्य एवं कौंसुली पद**

इस अभिसमय की किसी भी बात से अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत राजनयिक एजेंटों अथवा कौंसुली अधिकारियों के वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुच्छेद - 28**प्रवृत्त होना**

1. संविदाकारी राज्य इस अभिसमय को लागू करने के लिए अपने-अपने कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा किए जाने के बारे में एक-दूसरे को राजनयिक माध्यमों से लिखित रूप में अधिसूचित करेंगे ।
2. यह अभिसमय उस माह के अनुवर्ती दूसरे माह के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा जिस माह के बाद ये अधिसूचनाएं प्राप्त की गई थी ।
3. इस अभिसमय के उपबंध निम्नानुसार प्रभावी होंगे :
(क) भारत में : जिस कैलेंडर वर्ष में यह अभिसमय लागू होता है उसके अगले अनुवर्ती कैलेंडर वर्ष में पहली अप्रैल को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में ; और

(ख) सऊदी अरब में :

- (i) जिस कैलेंडर वर्ष में यह अभिसमय लागू होता है उसके अगले अनुवर्ती कैलेंडर वर्ष में पहली जनवरी को अथवा उसके बाद अदा की गई अथवा क्रेडिट की गई राशियों के संबंध में स्रोत पर धारित करों के संबंध में ;
- (ii) जिस कैलेंडर वर्ष में यह अभिसमय लागू होता है उसके अगले अनुवर्ती कैलेंडर वर्ष में पहली जनवरी को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी कराधेय वर्ष में अन्य करों के संबंध में ।

अनुच्छेद - 29

समापन

यह अभिसमय अनिश्चित समय तक लागू रहेगा जब तक कि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इसे समाप्त नहीं कर दिया जाता । दोनों में से कोई भी संविदाकारी राज्य इस अभिसमय के लागू होने की तारीख से लेकर पांच वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद किसी शुरू होने वाले कैलेंडर वर्ष की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले राजनयिक माध्यम से लिखित रूप में समापन का नोटिस देकर अभिसमय को समाप्त कर सकता है । ऐसी स्थिति में यह अभिसमय निम्न के संबंध में निष्प्रभावी हो जाएगा :

(क) भारत में, जिस कैलेंडर वर्ष में समापन का नोटिस दिया जाता है उसके अगले अनुवर्ती कैलेंडर वर्ष के पहली अप्रैल को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वित्त वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में ; और

(ख) सऊदी अरब में :

- (i) जिस कैलेंडर वर्ष में ऐसा नोटिस दिया जाता है उसके बाद अदा की गई अथवा क्रेडिट की गई राशियों के संबंध में तथा स्रोत पर धारित करों के संबंध में ;
- (ii) जिस कैलेंडर वर्ष में समापन का नोटिस दिया जाता है उसकी समाप्ति के बाद आरम्भ होने वाले किसी कराधेय वर्ष के संबंध में तथा अन्य करों के संबंध में ।

जिसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरियों ने, जो कि अपने संबंधित सरकारों की ओर से इसके लिए विधिवत् रूप से प्राधिकृत हैं, इस औद्योगिक पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में वर्ष 2006 के जनवरी माह के 25वें दिन, 25-12-1426एच के सदृश्य, हिन्दी, अरबी और अंग्रेजी भाषाओं में दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया है, इसके सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। अर्थ निरूपण की भिन्नता के मामले में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया
की सरकार की ओर से

प्रणव मुखर्जी
रक्षा मंत्री

इब्राहिम ए. अल-असाफ
वित्त मंत्री

प्रोतीकोल

भारत गणराज्य और सऊदी अरब किंगडम आय करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा कर अपवंचन को रोकने के लिए इस अभिसमय में को में निम्नलिखित उपबंधों पर सहमत हुए हैं, जो उक्त अभिसमय के अभिन्न अंग होंगे।

1. अनुच्छेद 3 के पैरा 2 (घ) के संबंध में, पद “व्यष्टि” में राज्य, इसके राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण तथा अन्य कोई हस्ती शामिल होगा जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के तहत कराधेय यूनिट के रूप में समझा गया है।

2. यह ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 2 के प्रयोजनार्थ, पद “कर” का तात्पर्य भारतीय अथवा सऊदी कर से है जैसा संदर्भानुसार अपेक्षित है, लेकिन इसमें उन करों के संबंध में लगाया गया कोई अर्थदण्ड अथवा जुर्माना शामिल नहीं होगा।

3. अनुच्छेद 3 के प्रयोजनार्थ, पद “वित्तीय वर्ष” का तात्पर्य है ;

- (i) भारत के मामले में, अप्रैल माह के प्रथम दिन को आरम्भ होने वाला वित्तीय वर्ष;
- (ii) सऊदी अरब के मामले में, सऊदी अरब किंगडम के कानून एवं विनियम में यथा निर्धारित कराधेय वर्ष।

4. यह समझा जाता है कि अनुच्छेद 4 के पैरा 1 (ख) के प्रयोजनार्थ, पद “निवासी” में निम्नलिखित शामिल होगा ;

- (क) सरकार की वैद्य संस्थानों एवं एजेंसियां जो प्रत्यक्ष रूप में पूर्णतः स्वामित्व में हों और सरकार द्वारा नियंत्रित हों।
- (ख) सऊदी अरब किंगडम के मामले में, कोई व्यक्ति, जो एक भारतीय राष्ट्रिक है और संबंधित वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर कम से कम 183 दिनों की अवधि या अवधियों के लिए सऊदी अरब किंगडम में उपास्थित है।
- (ग) किसी विधिक व्यक्ति जिसे एक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत संगणित किया गया है जिसे सामान्यतया उस राज्य में कर से छूट प्राप्त है तथा दोनों में से एक राज्य में संस्थापित एवं सम्पोषित किया गया है या तो ;

- (i) मुख्य रूप से किसी धार्मिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक अथवा अन्य इसी तरह के प्रयोजनार्थ ; अथवा
 - (ii) किसी योजना के अनुसार कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करने के लिए ।
5. अनुच्छेद 5 के पैरा 2 के प्रयोजनार्थ, स्थायी संस्थापन में निम्नलिखित शामिल होगा ;
- (क) कोई बिक्री बाजार ;
 - (ख) कोई फार्म, बागवानी अथवा कोई अन्य स्थान जहां पर कृषि, वानिकी, बागवानी अथवा इससे संबंधित क्रियाकलाप चलाए जाते हैं ।
6. अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 6 के प्रयोजनार्थ, कोई व्यक्ति, जो स्वतंत्र हैसियत का एक एजेंट नहीं है तथा जिसके कार्यकलाप बीमा उद्यम के लिए एक स्थायी संस्थापन को सृजन करें, या तो उस राज्य में कोई व्यक्ति अथवा कम्पनी होगा, उसकी ओर उस राज्य का न तो निवासी होने की और न ही कारोबार का कोई स्थल रखने की जरूरत ही होगी जहां वह उद्यम के लिए कार्य करता है ।
7. अनुच्छेद 7 के संबंध में, एक संविदाकारी राज्य के मामले में “कारोबार से लाभ” का तात्पर्य है, उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत तथा परिभाषित कारोबार से प्राप्त लाभ ।
8. अनुच्छेद 7 के संबंध में, यह समझा जाता है कि :
- (i) किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी संस्थापन के जरिए अथवा अन्यथा दूसरे संविदाकारी राज्य में पण्य-वस्तुओं के निर्यात संबंधी कारोबार से प्राप्त लाभ पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर नहीं लगाया जाएगा । जहां निर्यात संविदाओं में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए कार्यकलाप भी शामिल होते हों, वहां उस स्थायी संस्थापन द्वारा ऐसे कार्यकलापों से प्राप्त लाभों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा और केवल उसी लाभ पर कर लगाया जाएगा जो उस स्थायी संस्थापन के कारण ऐसी गतिविधियां से हुआ समझा जाए तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के बाहर निष्पन्न ऐसे कार्यकलापों के हिसाब पर स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करते समय इन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

- (ii) सर्वेक्षण, निर्माण अथवा अधिष्ठापन संबंधी संविदाओं के मामले में किसी स्थायी संस्थापन के लाभों को संविदा की कुल राशि पर निर्धारित नहीं किया जाएगा परन्तु इसका निर्धारण संविदा के उस भाग के आधार पर किया जाएगा जो उस राज्य में स्थायी संस्थापन द्वारा प्रभावी रूप से किया जाता है, जहां स्थायी संस्थापन स्थित हो और उस दूसरे राज्य में किए गए किसी समझौते के भाग को स्थायी संस्थापन के भागों का निर्धारण करते समय ध्यान में नहीं रखा जाएगा ।

9. अनुच्छेद 7 के पैरा 3 के प्रयोजनार्थ, एक संविदाकारी राज्य द्वारा दी जाने वाली व्ययों की कटौती तथा उस संविदाकारी राज्य के कर कानूनों की सीमाओं के अध्यधीन होगी और उन उपबंधों के अनुसार होगी । यदि भारत इस अभिसमय पर हस्ताक्षर करने के बाद किसी भी अभिसमय में इस प्रतिबंध को समाप्त कर देता है, तब दोनों पक्ष इस मूद्दे की पुनरीक्षा करेंगे ।
10. अनुच्छेद 21 के प्रयोजनार्थ, किसी व्यक्ति को एक संविदाकारी राज्य का निवासी तभी माना जाएगा यदि वह उस वित्त वर्ष के दौरान अथवा इसके तुरन्त बाद परवर्ती वित्त वर्ष में उस राज्य का निवासी हो जिस वित्त वर्ष के दौरान वह दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता हो ।
11. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ, जकत को आय पर कर के रूप में माना जाएगा ।
12. सऊदी अरब किंगडम के मामले में, अनुच्छेद 23 में दोहरे कराधान के परिहार हेतु सऊदी राष्ट्रिकों के संबंध में जकत वसूली प्रबंध के उपबंधों के विपरीत नहीं होंगी ।
13. यह समझा जाता है कि अनुच्छेद 25 में उल्लिखित सूचना में एक संविदाकारी राज्य के पास उपलब्ध वह साक्ष्य भी शामिल होगा जिसका दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा अनुरोध किया गया हो,
14. जब सऊदी अरब संधि के अन्य भागीदारों को करों की वसूली में सहायता प्रदान करने के लिए अथवा जब यह संधि के किसी अन्य भागीदार को ऐसी सहायता प्रदान करने के लिए सहमत होता है और वह अन्तर देशीय कानून में इस बाबत कोई उपबंध प्रस्तुत करता है, तब दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी को सहायता देने के लिए तौर-तरीकों को लागू करेंगे ।
15. यह समझा जाता है कि दोनों संविदाकारी राज्य इस अभिसमय के प्रवृत्त होने की तारीख से पांच वर्षों के बाद इस अभिसमय के उपबंधों की पुनरीक्षा करेंगे ताकि इस अभिसमय के कार्यक्षेत्र के भीतर ही तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अनुच्छेद को शामिल करने पर विचार किया जा सके ।

जिसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरियों ने, जो कि अपने संबंधित सरकारों की ओर से इसके लिए विधिवत् रूप से प्राधिकृत हैं, इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में वर्ष 2006 के जनवरी माह के 25वें दिन, 25-12-1426एच के सदृश्य, हिन्दी, अरबी और अंग्रेजी भाषाओं में दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया है, इसके सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। अर्थ निरूपण की भिन्नता के मामले में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया
की सरकार की ओर से

प्रणव मुखर्जी
रक्षा मंत्री

इब्राहिम ए. अल-असाफ
वित्त मंत्री

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th October, 2006

(INCOME TAX)

G.S.R. 645(E).—Whereas the annexed Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia for the avoidance of double taxation and the prevention of tax evasion with respect to taxes on income shall come into force on the 1st day of November, 2006, being the first day of the second month following the month in which the later of the notifications after completion of the procedures as required by the respective laws for the entry into force of this Convention was received, in accordance with Article 28 of the said Convention.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Convention shall be given effect to in the Union of India.

[Notification No. 287/2006-FTD/F. No. 501/7/91-FTD]

POONAM DUTT, Jt. Secy.

ANNEXURE**CONVENTION****BETWEEN****THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA****AND****THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA****FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE****PREVENTION OF****TAX EVASION****WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME**

The Government of the Republic of India and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia, desiring to conclude a Convention for the avoidance of double

taxation and the prevention of tax evasion with respect to taxes on income and with a view to promoting economic cooperation between the two countries, have agreed as follows:

Article 1

PERSONS COVERED

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, and taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises.
3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:
 - a) in the case of India:
 - The income tax, including any surcharge thereon;
(hereinafter referred to as "Indian tax");
 - b) in the case of the Kingdom of Saudi Arabia:
 - The Zakat
 - The income tax including the natural gas investment tax;
(hereinafter referred to as "Saudi tax").

4. The provisions of this Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either contracting state after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities in both Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in their respective taxation laws.

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:
 - a) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other jurisdiction, according to the Indian law and in accordance with international law, including the U.N. Agreement on the Law of the Sea;
 - b) the term "Kingdom of Saudi Arabia" means the territory of the kingdom of Saudi Arabia which also includes the area outside the territorial waters, where the Kingdom of Saudi Arabia exercises its sovereign and jurisdictional rights in their waters, seabed, subsoil and natural resources by virtue of its law and the international law;
 - c) the term "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean the Republic of India or the Kingdom of Saudi Arabia as the context requires;
 - d) the term "person" includes an individual, a company, any other body of persons.
 - e) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;
 - f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an

enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

- g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a contracting state, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
- h) the term "competent authority" means:
 - (i) In the case of India: The Finance Minister, Government of India or his authorized representative;
 - (ii) In the case of the Kingdom of Saudi Arabia, the Ministry of Finance represented by the Minister of Finance or his authorized representative;
- i) the term "national" means:
 - (i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;
 - (ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;

2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which this Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means

- (a) Any person who, under the laws of that State, is liable to taxes in that state by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. This term, however, does not

include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.

(b) The government of any of the two contracting states or any of its political subdivision or local authorities.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 of this Article an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

- a) he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both the Contracting States, he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
- b) if the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he does not have a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State in which he has a habitual abode;
- c) if he has a habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State of which he is a national;
- d) if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 of this Article a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective management is situated.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "Permanent Establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially:
 - a) a place of management;
 - b) a branch;
 - c) an office;
 - d) a factory;
 - e) a workshop;
 - f) a mine, a gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.
3. The term "permanent establishment" also includes:
 - (a) A building site, a construction, assembly or installation project, or supervisory activities, in connection therewith, but only where such site, project or activities continue for a period of more than 182 days;
 - (b) The furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only where activities of that nature continue (for the same or a connected project) within the country for a period or periods aggregating more than 182 days within any 12-month period.
4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:
 - (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
 - (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;
 - (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
 - (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
 - (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

- (f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies - is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person:

- a) has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph, or
- b) has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise;
- c) habitually obtains orders in the first-mentioned State, wholly or almost wholly for the enterprise itself.

6. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an insurance enterprise of a Contracting State shall be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in the territory of that other State or insures risks situated therein through a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies.

7. An enterprise of a contracting state shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be

considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

8. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning provided for in the laws of the Contracting State in which the property in question is situated. This term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 of this Article shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 of this Article shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7**BUSINESS PROFITS**

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.
2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.
3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission, for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of income from debt-claim with regard to moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the permanent

establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of income from debt-claim with regard to moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbor of the ship is situated, or, if there is no such home harbor, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.

3. The term "profits derived from the operation of ships or aircraft in international traffic" includes profits derived from the use or rental of containers and related equipment used in international transport that is incidental to income from the operation of ships or aircraft in international traffic.
4. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.
5. Nothing contained in the foregoing provisions of this Article shall affect the existing Agreement between the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of India for Avoidance of Double Taxation by reciprocal exemption of taxes on income on the Activities of Air Transport Enterprises signed on 14.11.1991 in respect of Air India and Saudi Arabian Airlines Corporation.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where

- a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, and by reason of those

conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed 5 percent of the gross amount of the dividends. This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from

other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

INCOME FROM DEBT-CLAIMS

1. Income from debt-claims arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such income from debt-claims may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that Contracting

State, but if the beneficial owner of the income from debt-claims is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the income from debt-claims.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, income from debt-claims arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State, provided that it is derived and beneficially owned by:

- a) the Government, a political sub-division or a local authority of the other Contracting State; or
- b) (i) in the case of India, the Reserve Bank of India, the Export-Import Bank of India, the National Housing Bank ; and
(ii) in the case of the Kingdom of Saudi Arabia, the Saudi Arabian Monetary Agency; or
- c) any other financial institution wholly owned directly, and controlled by the Government of the other Contracting State.

4. The term "Income from Debt-Claims" as used in this Article means income from government securities and bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits; and debt-claims of every kind as well as all other income included as income from moneys lent under the taxation laws of the State in which the income arises. Penalty charges for late payment shall not be regarded as income from debt-claims for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of income from Debt-Claims, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the income from debt claims arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that

other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt claim in respect of which such income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Income from debt-claims shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying such income, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which such income is paid was incurred, and such income is borne by such permanent establishment or fixed base, then such income shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the income from debt-claims, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that Contracting State, but if the

beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraph 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the

beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other Contracting State.
3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic, or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.
4. Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that State.
5. Gains from the alienation of shares other than those mentioned in paragraph 4 in a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that State.

6. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of a independent character shall be taxable only in that State except in the following circumstances when such income may also be taxed in the other Contracting State:

- a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; or
- b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in any 12 – month period commencing or ending in the fiscal year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, surgeons, dentists and accountants.

Article 15**DEPENDENT PERSONAL SERVICES**

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

- a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and
- b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
- c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.

Article 16**DIRECTORS' FEES**

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17**ARTISTES AND SPORTSPERSONS**

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2, shall not apply to income from activities performed in a Contracting State by entertainers or sportspersons if the activities are substantially supported by public funds of one or both of the Contracting States or of political subdivisions or local authorities thereof or takes place under a cultural agreement or arrangement between the Governments of the

Contracting States. In such a case, the income shall be taxable only in the Contracting State of which the entertainer or sports person is a resident.

Article 18

PENSIONS

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

Article 19

GOVERNMENT SERVICE

1. a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who:

- (i) is a national of that State; or
- (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that other State.

3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 shall apply to salaries, wages and other similar remuneration and to pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

Article 20

STUDENTS

1. Payments, besides grants, loans and scholarships, which a student, trainee or apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

2. Payments received by a student, trainee or apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training and which constitute remuneration in respect of services performed in that other Contracting State are not taxable in that other State, provided the services are connected with education or training and are necessary for maintenance purposes.

3. The benefits of this Article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefits of this Article, for more than six consecutive years from the date of his first arrival in that other State.

Article 21

TEACHERS AND RESEARCHERS

1. A teacher or researcher who is or was a resident of the Contracting State immediately before being invited to or visiting the other Contracting State for the purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university, college or other similar institution in that other Contracting State shall be exempt from tax in that other State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his arrival in that other State.
2. This Article shall apply to income from research only if such research is undertaken by the individual in the public interest.

Article 22

OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that Contracting State.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

Article 23**METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION**

Double taxation shall be eliminated as follows:

1. Where a resident of a Contracting State derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in the other Contracting State, the first mentioned Contracting State shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the tax paid in the other Contracting State.

Such deduction shall not, however, exceed that portion of the tax as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income which may be taxed in the other Contracting State.

2. Where in accordance with any provision of the Convention income derived by a resident of a Contracting State is exempt from tax in that Contracting State, that Contracting State may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.

Article 24**MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE**

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. The case must be presented within three years

from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of this Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with this Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of both Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of this Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in this Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 25

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as

information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to the taxes covered by this Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

Article 26

OTHER PROVISIONS

1. Nothing in this Convention shall affect the application of the domestic provisions to prevent tax evasion.

2. An enterprise of a Contracting State shall not be entitled to the benefits of this Convention if the main purpose or one of the main purposes of the creation of

such enterprise was to obtain the benefits under this convention that would not otherwise be available.

3. The case of legal entities not having bonafide business activities shall be covered by the provisions of this Article.

Article 27

MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28

ENTRY INTO FORCE

1. The Contracting States shall notify each other in writing, through diplomatic channels, of the completion of the procedures required by the respective laws for the entry into force of this Convention.
2. This Convention shall enter into force on the first day of the second month following the month in which the later of these notifications was received.
3. The provisions of this Convention shall have effect:
 - (a) In India, in respect of income derived in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the Convention enters into force; and

(b) In Saudi Arabia:

- i) with regard to taxes withheld at source, in respect of amounts paid or credited on or after the first day of January next following the Calendar Year in which the Convention enters into force; and
- ii) with regard to other taxes, in respect of taxable years beginning on or after the first day of January next following the calendar year in which the Convention enters into force.

Article 29

TERMINATION

This Convention shall remain in force indefinitely until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year beginning after the expiration of five years from the date of entry into force of the Convention. In such event, the Convention shall cease to have effect:

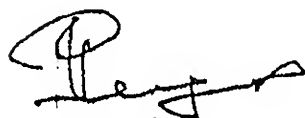
- a) In India, in respect of income derived in any fiscal year on or after the first day of April next following the calendar year in which the notice is given;
- b) In Saudi Arabia
 - (i) with regard to taxes withheld at source, in respect of amounts paid or credited after the end of the calendar year in which such notice is given; and
 - (ii) with regard to other taxes, in respect of taxable years beginning after the end of the calendar year in which such notice is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Convention.

DONE in duplicate at New Delhi, this 25th day of January, 2006, corresponding to 25 -12 -1426 h, each in the Hindi, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the
Republic of India

For the Government of the
Kingdom of Saudi Arabia



PRANAB MUKHERJEE
Defence Minister



IBRAHIM A. AL-ASSAF
Minister of Finance

PROTOCOL

The Republic of India and the Kingdom of Saudi Arabia on signing at New Delhi, on 25th January, 2006, the Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Tax Evasion with respect to taxes on Income have agreed upon the following provisions which shall form an integral part of the said Convention.

1. With regard to para 2(d) of Article 3 the term 'person' shall include the state, its political sub-division or local authorities and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States.
2. It is understood that for the purposes of Article 2, the term "tax" means Indian or Saudi tax, as the context requires, but shall not include any penalty or fine imposed relating to those taxes.
3. For the purposes of Article 3, the term "fiscal year" means:
 - i) in the case of India: the financial year beginning on the 1st day of April;

- ii) in the case of Saudi Arabia: taxable year as determined in the law and regulation of the Kingdom of Saudi Arabia.
4. It is understood that for the purposes of para 1(b) Article 4, the term 'resident' shall include:
- (a) the legal institutions and agencies of the Government, wholly owned directly, and controlled by the Government.
 - (b) In the case of the Kingdom of Saudi Arabia, an individual who is an Indian national and is present in the Kingdom of Saudi Arabia for a period or periods totaling in the aggregate at least 183 days in the fiscal year concerned.
 - (c) A legal person organized under the laws of a Contracting State and that is generally exempt from tax in that State and is established and maintained in that State either:
 - i) Exclusively for a religious, charitable, educational, scientific, or other similar purpose; or
 - ii) To provide pensions to employees pursuant to a plan.
5. For the purposes of para 2 of Article 5, Permanent Establishment shall include the following:
- a) a sales outlet;
 - b) a farm, plantation or other place where agricultural, forestry, plantation or related activities are carried on.
6. For the purposes of paragraph 6 of Article 5, the person, who is not an agent of independent status and whose activities may create a Permanent Establishment for the insurance enterprise, may be either individual or company and need not be resident of, nor have a place of business in, the state in which it acts for the enterprise.
7. With regard to Article 7, the term 'business profits' in the case of a Contracting State means the profits from business as defined under the laws of that Contracting State.

8. In respect of Article 7, it is understood that: -

(i) the business profits derived by an enterprise of a Contracting State whether through a permanent establishment situated in the other Contracting State or otherwise from the exportation of merchandise to the other Contracting State shall not be taxed in that other Contracting State. Where export contracts include other activities carried on in the other Contracting State, profits derived by the Permanent Establishment from such activities may be taxed in the other Contracting State but only so much of the profits as is attributable to the permanent establishment, relating to such other activities and any portion of these activities executed outside the other Contracting State shall not be taken into consideration in determining the profits of the permanent establishment.

(ii) In the case of contracts for survey, constructions or installations, the profits of a permanent establishment shall not be determined on the total amount of the contract, but shall be determined only on the basis of that part of the contract, which is effectively carried out by the permanent establishment in the state where the permanent establishment is situated and any portion of the contract executed outside the other Contracting State shall not be taken into consideration in determining the profits of the permanent establishment.

9. For the purposes of Para 3 of Article 7, the deductions of expenses to be allowed by a Contracting State shall be in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the tax laws of that Contracting State. In case India removes this restriction in any of its Conventions after the date of signing of this Convention, the two sides shall review this issue.

10. For the purposes of Article 21, an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is resident in that State in the fiscal year in which he visits the other Contracting State or in the immediately preceding fiscal year.

11. For the purposes of this Convention, the Zakat shall be treated as a tax on income.

12. In the case of the Kingdom of Saudi Arabia, the methods for elimination of double taxation in Article 23 will not prejudice the provisions of the Zakat collection regime with regard to Saudi nationals.

13. It is understood that information referred to in Article 25, will include evidence available with a Contracting State, requested by the other Contracting State.

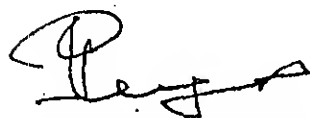
14. When Saudi Arabia introduces a provision in its domestic law regarding assistance in collection of taxes to other treaty partners or agrees to extend such assistance to any other treaty partner, then the competent authorities of the two Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application for extending assistance in the collection of tax to each other.

15. It is understood that the two Contracting States will review the provisions of this Convention after a period of 5 years from the date on which this Convention enters into force in order to consider the inclusion of an Article on 'Fees for Technical Services' within the scope of this Convention.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at New Delhi, this 25th day of January, 2006, corresponding to 25 -12 -1426 h, each in the Hindi, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the
Republic of India



PRANAB MUKHERJEE
Defence Minister

For the Government of the
Kingdom of Saudi Arabia



IBRAHIM A. AL-ASSAF
Minister of Finance